

ccw
8/4/16

सपत्रांक- 2495 न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् सीतामढ़ी

पटना, दिनांक 8/4/16

विषय :- माह फरवरी 2016 की मासिक समीक्षा टिप्पणी के संबंध में।

महाशय,

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आपके कार्यों की मासिक समीक्षा की जा रही है। माह फरवरी तक प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा से निम्न तथ्य विदित होते हैं :-

1. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग :-

(i) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय में 380.54 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2015-16 में 14.00 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 394.54 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 316.70 लाख रुपये है, जो मात्र 80.27 प्रतिशत है। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि **संतोषजनक** है।

2. 13वें वित्त आयोग :-

(i) 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय में 77.36 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2015-16 में 50.77 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 128.13 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 58.74 लाख रुपये है, जो मात्र 45.84 प्रतिशत है।

(ii) भौतिक प्रतिवेदन की समीक्षा करने से ज्ञात है कि दिनांक 01.04.2015 को 1 योजनाएं लंबित थी। वर्ष 2015-16 में अब तक 17 योजना ली गयी है। इस प्रकार कुल कार्यरत 18 योजना में से 11 योजनाएं पूर्ण हुई हैं। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि **असंतोषजनक** है।

3. 14 वें वित्त आयोग

14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय में 76.06 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2015-16 में 74.98 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 151.04 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 2.00 है। जो की 1.32 प्रतिशत है।

4. राज्य योजना :-

- (i) राज्य योजना अंतर्गत दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय में 136.35 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2015-16 में 416.72 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 553.07 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 77.28 लाख रुपये है, जो की 13.97 प्रतिशत है।
- (ii) भौतिक प्रतिवेदन की समीक्षा करने से ज्ञात है कि दिनांक 01.04.2015 को 8 योजना लंबित थी। वर्ष 2015-16 में अब तक 10 योजना ली गयी है। इस प्रकार कुल कार्यरत 18 योजना में से 8 योजना पूर्ण हुई है। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि **संतोषजनक** है।

5. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) :-

- (i) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय में 141.56 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2015-16 में 33.78 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 175.24 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 63.48 लाख रुपये है, जो मात्र 36.22 प्रतिशत है।
- (ii) भौतिक प्रतिवेदन की समीक्षा करने से ज्ञात है कि दिनांक 01.04.2015 को 10 योजना लंबित थी। वर्ष 2015-16 में अब तक 2 योजना ली गयी है। इस प्रकार कुल कार्यरत 12 योजना में से 9 योजना पूर्ण हुई है। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि **निराशाजनक** है।

6. ठोस अवशिष्ट प्रबंधन :-

- (i) आपके शहर में कुल 28 वार्ड हैं, जिसमें से अभी तक किसी भी वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य नहीं हो रहा है।
- (ii) सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यांत्रिकरण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन वांछित संख्या में मशीनों का क्रय नहीं किया गया है। शहर में कार्यरत सफाई कर्मियों की ससमय उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमिट्रिक हाजिरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, इसका अनुपालन अप्राप्त है। ठोस अवशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन एवं निष्पादन के लिए की जा रही कार्रवाई का प्रतिवेदन अपेक्षित है।

7. मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान :-

- (i) मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान योजना के अंतर्गत दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय में 0.00 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2015-16 में 76.31 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 76.31 लाख रुपये संसाधनों में से दूरभाष पर प्राप्त सूचना के अनुसार अद्यतन व्यय 0.00 लाख रुपये है।

8. उपयोगिता प्रमाण पत्र :-

आपके निकाय के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2014-15 तक की अवधि में कुल 4528.58 लाख की राशी विभाग द्वारा आवंटित की गयी थी जिसके आलोक में अभी तक कुल 1886.50 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा की गयी है और 2500.29 लाख की राशि अभी तक समायोजित के लिए लंबित हैं। लंबित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले 7 दिनों के अंदर विभाग में जमा करें | 62.92 लाख की राशि प्रशासनिक भवन मद की है, यह राशि व्ययगत है। (पत्रांक-15 दिनांक-03.01.15)

9. नगर सेवा प्रबंधन :-

आपके शहर से संबंधित इस वित्तीय वर्ष में हेल्पलाईन के माध्यम से 6 जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 4 का निराकरण किया गया है, एवं 2 लंबित हैं। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि **संतोषजनक** है।

10. होल्डिंग टैक्स :-

माह फरवरी 2016 का मासिक संग्रहण 13.08 लाख रुपये है, जो की वित्तीय वर्ष की औसत मासिक संग्रहण 3.08 लाख रुपये से शत प्रतिशत अत्यधिक है। चालू वित्तीय वर्ष का वार्षिक औसत मासिक संग्रह 5.01 है | दिनांक 01.04.2015 को होल्डिंग की संख्या 8510 थी एवं अद्यतन तिथि तक 9048 होल्डिंग ही है। होल्डिंग का सर्वेक्षण करके अतिरिक्त होल्डिंग को होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाने के लिए किये गये प्रयास जारी रहे। स्पष्टतः अब तक उपलब्धि **अत्यन्त निराशाजनक** है।

11. अन्य स्रोतों से कर :-

अन्य स्रोतों से कर वसूली 11.98 लाख रुपये है, जिसमें सुधार लाने का प्रयास करें।

12. शौचालय निर्माण :-

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिए गए कुल लक्ष्य 1099 के विरुद्ध आपके निकाय में कोई भी Public Toilet नहीं बने हैं, एवं अभी तक कोई भी सामूहिक शौचालय नहीं बने हैं। इस पर जोर दिया जाय।

13. सबके लिए आवास :- सबके लिए आवास योजनान्तर्गत आपके नगर निकाय में वित्तीय वर्ष

2015-16 में कुल प्राप्त आवेदन में से अधतन स्थिति तक जचोपरांत लाभार्थियों की संख्या 0 है।

14 पी०एल० खाता:- दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय के पी० एल० खाते में 1549.02 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2015-16 में 647.95 लाख राशि विमुक्त की गई है। इस प्रकार कुल उपलब्ध 2196.97 लाख की राशि में से 1088.72 लाख मात्र राशि का भुगतान किया गया

है शेष 1108.25 लाख की अव्यवहृत अंतिम राशि (Closing Balance) अभी भी मौजूद है जो अत्यंत ही बड़ी राशि है।

15. लंबित अंकेक्षण :-

आपके नगर निकाय के विरुद्ध निम्नलिखित अंकेक्षण प्रतिवेदन लंबित है :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	अप्राप्त
95 / 2001-02	1997-1998 से 2000-01	अप्राप्त
206 / 2007-08	2001-02 से 2005-06	अप्राप्त

निर्देश दिया जाता है कि इस मासिक समीक्षा टिप्पणी में अंकित तथ्यों पर लिखित अनुपालन प्रतिवेदन पत्र निर्गत होने के तीन सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से विभाग को प्रेषित किया जाय। इस मासिक समीक्षा टिप्पणी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। साथ ही आपके द्वारा समर्पित किये जा रहे मासिक समीक्षा टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव।

पटना, दिनांक 8/4/16

ज्ञापांक-2495 /

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/अध्यक्ष नगर परिषद् सीतामढ़ी एवं विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।